सेवा संकल्प अभियान से परिवर्तन की गाथा नई पीढ़ी तक पहुँचाएँ- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय में "सेना संकल्प अभियान" की प्रदेश कार्यशाला में भाग लिया

जयपुर, 12 सितंबर। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से प्रदेशभर में "सेवा संकल्प अभियान-जन सेवा ही प्रभु सेवा" का शुभारंभ करेगी। अभियान की प्रदेश कार्यशाला शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई। कार्यशाला में अभियान की तैयारियों, कार्यक्रमों एवं संगठनात्मक रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई।

■ कार्यशाला में 17 सितंबर से शुरु होने वाले अभियान की विस्तृत रूपरेखा और तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह कार्यक्रम 3 प्रकल्पों के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से प्रदेशभर में होने वाले "सेवा संकल्प अभियान-जन सेवा ही प्रभु सेवा" अभियान की तैयारियों को लेकर आयोजित हुई प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है, जो जनकल्याण, गरीब, युवा, महिला और किसान के उत्थान तथा देश-दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने की सोच के साथ राजनीति को सेवा का माध्यम मानकर कार्य कर रहा है। ऐसे सेवाभावी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व सदियों में मिलता है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद का भारत परिवर्तनकारी भारत रहा है, जबकि इससे पहले देश भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और आतंकवाद जैसी समस्याओं से घिरा हुआ था। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से इस परिवर्तन की गाथा नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर बड़ी उम्मीद से देखती है और हमें जनता की उस उम्मीद को पूरा करना है।

उन्होंने कहा कि भाजपा परिवारवाद से परे हटकर "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" की भावना के साथ कार्य करती है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि "सेवा संकल्प अभियान" के तहत 17 सितंबर से प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान की क्षेत्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉ. कविता पाटीदार ने प्रदेश कार्यशाला में 17 सितंबर से शुरू होने वाले अभियान की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 13 प्रकल्पों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

डॉ. पाटीदार ने बताया कि अभियान का शुभारंभ "आशीर्वाद का दीया" कार्यक्रम से होगा। 17 सितंबर को शाम 7 बजे प्रत्येक घर, विशेषकर केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के घरों में दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे।

भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के चहुंमुखी विकास और सेवा की गाथा को प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक टोलियां बनाकर जन-जन तक पहुंचाना होगा। प्रत्येक अभियान में सरकार के मंत्रियों, भाजपा संगठन के पदाधिकारियों एवं संबंधित जिलों के सदस्यों को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।

उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, जोगाराम कुमावत, मंजू बाघमार, सुमित गोदारा, संजय शर्मा, सुरेश रावत, अविनाश गहलोत, गौतम दक एवं हेमंत मीणा सहित, भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों को विभिन्न अभियानों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

कार्यशाला में मध्यप्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद एवं "वडनगर से वाराणसी सेवा यात्रा" के राष्ट्रीय प्रभारी वी.डी. शर्मा तथा उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा मंच पर उपस्थित रहे। कार्यशाला का संचालन भाजपा महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने किया।

पिथौरागढ़ में बैली ब्रिज बहा, चीन की सीमा से लगी घाटियों से सम्पर्क टूटा

नई दिल्ली, 12 सितंबर। देशभर में मौसम और भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कुलागाड़ नाले पर बना 170 फीट लंबा बैली ब्रिज तेज बहाव में बह गया है, जिससे चीन सीमा से लगी घाटियों का संपर्क टूट गया है। वहीं, छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में हसदेव नदी में सेल्फी लेने के चक्कर में 3 कॉलेज छात्र तेज बहाव में बह गए, जिनकी तलाश जारी है।

■ बिहार में 47 लाख लोग बाढ़ की चपेट में, गंगा खतरे के निशान के ऊपर

मैदानी इलाकों की बात करें तो यूपी और बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। बिहार में 47 लाख और यूपी में 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं और गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उधर, मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

पिथौरागढ़ में धारचूला के आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर गस्कू के पास अचानक पहाड़ी से बोल्डरों की बरसात होने से शुक्रवार को करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा था। पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिरते देख मौके पर काम कर रहे जेसीबी ऑपरेटर ने सूझबूझ दिखाते हुए मशीन को तत्काल सुरक्षित स्थान पर हटा लिया। इससे बड़ा हादसा टल गया।

बिहार में बाढ़ से 15 जिलों में 47 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। गंगा समेत, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश के 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 4 लाख की आबादी प्रभावित है। 21 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कानपुर-उन्नाव में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। नदी के किनारे पर बने गांवों में 10 फीट तक पानी भर गया है।

भारत व ब्राज़ील को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को रुस-चीन का समर्थन

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जारी नई दिल्ली घोषणापत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पुनर्गठन की मांग की

नई दिल्ली, 12 सितंबर। भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शनिवार को 140 बिंदुओं वाला नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के पुनर्गठन की मांग करते हुए वैश्विक संस्थाओं में सुधार, एकतरफा दंडात्मक व्यापारिक प्रतिबंधों जैसे 'टैरिफ' को समाप्त करने, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व में असमानता दूर करने और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद पर महिला एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की जरूरत पर जोर दिया गया। वीटो पावर वाले चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत तथा ब्राजील की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है।

■ ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत लगाये जाने वाले एकतरफा दंडात्मक उपायों और आर्थिक व द्वितीयक प्रतिबंधों की निन्दा की और कहा कि इसका असर आम आदमी के मानवाधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा व विकास के अधिकार पर पड़ता है।

ब्रिक्स देशों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, सीमा पार आतंकवाद और आतंक के वित्तपोषण के खिलाफ कार्रवाई तथा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सम्मेलन को जल्द अपनाने की भी अपील की गई।

भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने एकतरफा टैरिफ और व्यापारिक पाबंदियों पर चिंता जताई। कहा कि ऐसे कदम डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुरूप होने चाहिए। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, क्षेत्रीय संघर्षों और ग्लोबल साउथ की बढ़ती भूमिका के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और वैश्विक व्यापार व्यवस्था को मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने की बात कही गई है।

ब्रिक्स देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत लगाए जाने वाले एकतरफा दंडात्मक उपायों और आर्थिक तथा द्वितीयक प्रतिबंधों की निंदा की। बयान में कहा गया कि इनका असर आम आबादी के मानवाधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और विकास के अधिकार पर पड़ता है तथा गरीब और कमजोर वर्ग अधिक प्रभावित होते हैं। ब्रिक्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना लगाए गए ऐसे प्रतिबंधों सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत सभी एकतरफा दंडात्मक उपायों को समाप्त करने की मांग की। व्यापार के मोर्चे पर नेताओं ने गैर-टैरिफ बाधाओं और भेदभावपूर्ण कार्बन शुल्कों पर चिंता जताई तथा वैश्विक व्यापार व्यवस्था को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। सीमा पार भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाने, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने और ब्रिक्स भुगतान कार्यबल की प्रगति का स्वागत किया गया। वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति की भी जानकारी दी गई। नए विकास बैंक के काम की सराहना करते हुए बुनियादी ढांचे और सतत विकास के वित्तपोषण को बढ़ाने पर जोर दिया गया।

चीन की ग्वांगझोड -दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बेहतर हवाई संपर्क ऐसे रिश्तों के लिए क्या कर सकता है, जो लंबे समय से भरोसे की भारी कमी से जूझ रहे हैं। 2020 के सीमा संकट के बाद कई वर्षों तक, कारोबारी यात्रियों, छात्रों, पर्यटकों और पेशेवरों को सीमित सीधी उड़ानों और तीसरे देशों के रास्ते लंबी और मुश्किल यात्राओं का सामना करना पड़ा। सीधी उड़ानों की बहाली से यात्रा का समय और परेशानियां, दोनों कम होंगी। इससे व्यापारिक गतिविधियों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ने की संभावना है।

ग्वांगझोउ खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दक्षिणी चीन का प्रमुख व्यापारिक और मैन्यूफैक्चरिंग हब है तथा "पर्ल रिवर डेल्टा" क्षेत्र का एक बड़ा प्रवेश द्वार है।

बेहतर और आसान हवाई संपर्क से भारतीय कंपनियों और चीनी निर्माताओं, सप्लायरों तथा प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच संपर्क बढ़ सकता है। इससे पर्यटन, शिक्षा और प्रोफेशनल स्तर पर आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिल सकता है।

फिर भी, हवाई संपर्क की इस बहाली को इस बात के प्रमाण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि दोनों देशों के रणनीतिक मतभेद खत्म हो गए हैं। सीमा विवाद अभी भी सुलझा नहीं है, सैन्य तैनाती जारी है और संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी निवेश को लेकर भारत अभी भी सतर्क है। व्यापार भी काफी बढ़ा है, लेकिन व्यापार में असंतुलन और चीनी आयात पर निर्भरता अब भी नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय है।

भारत और चीन के लिए हवाई कनैक्टिविटी रणनीतिक मतभेदों के समाधान का विकल्प नहीं है। लेकिन इससे ऐसा माहौल जरूर बन सकता है, जिसमें बातचीत, व्यापार और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क आसान हो। इसलिए इस उड़ान सेवा की बहाली एक छोटा, लेकिन स्पष्ट संकेत है कि दोनों एशियाई शक्तियां टकराव से हटकर सावधानीपूर्वक साथ रहने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

विधानसभा चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। इसलिए वह राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं रह सकता था। इसके अलावा इस्तीफा वापस लेने की अनुमति देने से उसे निरंतर सेवा में रहा हुआ माना जाता, जिसका मतलब यह होता की वह अपनी सेवा अवधि के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त माना जाता। जबकि 1964 के नियमों में प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा।

जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश नीरज बिश्नोई की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए।

याचिका में नीरज विश्नोई ने कहा था कि वह उत्तर-पश्चिम रेलवे में सीनियर ऑडिटर के पद पर कार्यरत था। उसने विगत विधानसभा चुनाव लडने के लिए 10 अक्टूबर, 2023 को इस्तीफा दिया था और विभाग ने 1 नवंबर को उसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसने चूरू के रतनगढ विधानसभा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लडा, लेकिन वह हार गया। चुनाव परिणाम आने के बाद एक जनवरी को उसने इस्तीफा वापस लेने और सेवा में बहाली के लिए आवेदन दिया।

हरीश रावत का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भर्ती बोर्ड और शिक्षा भर्ती बोर्ड सहित, भर्ती बोर्डों का गठन भी किया।"

रावत ने कहा, "अगर इस प्रक्रिया के दौरान नियुक्तियों के संबंध में हमारी ओर से कोई निर्णय संबंधी गलती हुई हो, तो मैं उत्तराखंड की जनता से माफी मांगता हूं। लेकिन मैं सम्मानपूर्वक अपने इस दावे को दोहराना चाहता हूं कि हमारे तीन साल के कार्यकाल के दौरान 42,000 से अधिक सरकारी पद भरे गए थे।"

रावत ने कहा कि यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष के रुप में नियुक्त व्यक्ति का चयन उसके पिछले सेवा रिकॉर्ड के आधार पर किया गया था। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद उन्होंने खुद अध्यक्ष को हटा दिया था या उनसे इस्तीफा मांगा था।

उन्होंने कहा, अगर मैंने जानबूझकर या अनजाने में ऐसा कोई काम किया है, जिससे हमारे राज्य के युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है, तो मैं खुद को उसके लिए सजा का पात्र मानता हूं। ऐसी किसी भी चूक के लिए मैं उत्तराखंड की जनता से माफी मांगता हूं।

रावत ने सार्वजनिक अपील करते हुए कहा कि अगर किसी के पास नियुक्तियों या भर्ती प्रक्रियाओं में उनके हस्तक्षेप से जुड़े कोई सबूत हैं, तो उन्हें सीबीआई, ईडी या राज्य पुलिस को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

यूक्रेन में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

(आरटी) के अनुसार, पुतिन ने कहा कि रूस यूरोपीय देशों को धमकी नहीं दे रहा है और न ही ऐसा करने की उसकी कोई योजना है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यूक्रेन में यूरोपीय नाटो देशों की सैन्य मौजूदगी संघर्ष को रूस और पश्चिम के बीच सीधे टकराव में बदल सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ यूरोपीय देश यूक्रेन में सैनिक भेजने पर विचार कर रहे हैं। रूस पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि सुरक्षा गारंटी या शांति मिशन के नाम पर नाटो देशों की यूक्रेन में सैन्य तैनाती स्वीकार्य नहीं होगी। पुतिन ने यूरोप की मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के लिए पश्चिमी देशों के नेतृत्व की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि शीत युद्ध के बाद विदेश नीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसलों में यूरोपीय नेताओं ने सिस्टम से जुड़ी कई गलतियां कीं, जिनका असर अब दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी नेतृत्व और वैश्विक अभिजात वर्ग को विश्वास हो गया था कि वे सत्ता और प्रभाव के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं और उनसे गलतियां नहीं हो सकतीं।

मायावती अपनी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समय लंदन में वकालत की पढ़ाई कर रही हैं। दीपिका के पिता आनंद कुमार बसपा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनकी गिनती पार्टी के ताकतवर नेताओं में होती है। आनंद कुमार पर्दे के पीछे काम करने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। शनिवार को मायावती की ओर से दीपिका आनंद का नाम लिए जाने के बाद अब राजनीति में इस नाम की चर्चा तेज हो गई है।

यमन, सऊदी अरब की ओर देखता रहा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिए एयर सपोर्ट देने की गुहार लगा रहा था। दूसरी ओर, सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन सरकार भी सऊदी सेना से हस्तक्षेप करने और हूथी विद्रोहियों के हमले को रोकने के लिए एयर पावर देने की मांग कर रही थी।

लेकिन हूथी विद्रोहियों के समूह को रोकने की कोशिश करने के बजाय, वे दूर खड़े रहे और उन्होंने उंगली तक नहीं उठाई। विडंबना यह है कि जब मध्य पूर्व की स्थिति गंभीर संकट की ओर बढ़ रही थी, तब पूरे घटनाक्रम की शुरुआत करने वाले डॉनल्ड ट्रंप दुनिया के दूसरे हिस्सों में नए विवाद खड़े करने में व्यस्त थे। ट्रंप ने उत्तरी (कैथोलिक) आयरलैंड को दक्षिणी (प्रोटैस्टैंट-एंग्लिकन) आयरलैंड के साथ मिलाने की बात करके आयरलैंड के बंटवारे के विवादास्पद मुद्दे को फिर से हवा दे दी। इस विवाद के कारण दशकों तक हिंसा और खून-खराबा हुआ था।

अमेरिका या सऊदी अरब में से किसी भी पक्ष की ओर से कोई सहायता या सैन्य हस्तक्षेप नहीं आया, जबकि इनको हूथियों से यमन लोगों की रक्षा करनी थी। हूथी सेनाओं ने बिना किसी रोक-टोक के दक्षिणी यमन में आगे बढ़ते हुए तटीय बंदरगाह के साथ-साथ उस महत्वपूर्ण द्वीप पर भी कब्जा कर लिया, जो बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के बीच एक चौकी की तरह स्थित है।

यह महत्वपूर्ण स्थान लाल सागर से हिंद महासागर के व्यापक समुद्री क्षेत्र में आने-जाने के पूरे मार्ग पर नियंत्रण रखता है। यह मार्ग स्वेज नहर के जरिए एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली मुख्य कड़ी है। ईरान व अमेरिका के बीच टकराव के कारण जब होर्मुज़ जलडमरूमध्य का वैकल्पिक रास्ता बंद हो गया, तब इस रास्ते का महत्व और बढ़ गया। इस समुद्री मार्ग पर किसी भी तरह की रूकावट से केवल तेल की आवाजाही ही प्रभावित नहीं होगी, बल्कि सामान्य माल की आवाजाही में भी समस्याएं पैदा होंगी। ईरान के समर्थन वाले हूथियों की तेजी से हुई इस कार्यवाही ने ईरानियों को समुद्री मार्ग पर बहुत ज्यादा नियंत्रण दे दिया है, जिससे पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में आपातकाल जैसी नई स्थिति पैदा हो गई है।

ब्रिक्स देश नाविक आपातकालीन सहायता नेटवर्क बनायें-मोदी

नई दिल्ली, 12 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नाविकों की सुरक्षा के लिए ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच नाविक आपातकालीन सहायता नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने ब्रिक्स देशों से समुद्री यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए समुद्री सुरक्षा नेटवर्क बनाने की बात कही।

आजमगढ़ में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

लखनऊ, 12 सितंबर। उत्तर प्रदेश के एंटी टैररिस्ट स्क्वॉड ने आजमगढ़ से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन "अल कायदा इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट" की विचारधारा से प्रेरित और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है।

■ वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल कायदा की गतिविधियों में लिप्त था।

एटीएस ने शनिवार को जारी किए गए बयान में बताया कि आजमगढ़ जिले के ग्राम चितारा निवासी मोहम्मद नबील के मोबाइल फोन को कब्जे में लिया गया। उसके मोबाइल फोन की जांच में पाया गया कि वह अलकायदा के आतंकी अनवर उल अवलाकी की विचारधारा से प्रेरित है। उसके मोबाइल पर एक व्हाटसअप ग्रुप भी मिला है, जिसमें वह नये-नये लड़कों को जोड़ता था और उसमें जुड़े सदस्यों को वह मुजाहिद कहके संबोधित करता था। ग्रुप में आतंकी अनवर उल अवलाकी की लिखी किताब भी शेयर करते हुए उसे लोगों से पढ़ने की अपील की गई है। वह और भी कई ग्रुप में जुड़ा है, जिसमें मोहम्मद नबील ने दूसरे देश पाकिस्तान, तुर्की तथा बांग्लादेश में जाकर अपने मकसद को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग एवं बम आदि बनाने की विधि से संबंधित वीडियो और अन्य चीजें बरामद की जा रही हैं। एटीएस की टीम अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है।

मोदी-शी बातचीत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फिर से मजबूत करने में रुचि रखता है।

सीधी हवाई सेवा की धीरे-धीरे बहाली और वीजा प्रतिबंधों में कुछ ढील देना इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। भारत और चीन के शहरों के बीच उड़ानों के फिर से शुरु होने से कारोबार, पर्यटन, शिक्षा और प्रोफेशनल स्तर पर लोगों की आवाजाही बढ़ सकती है, जिससे 2020 के बाद दोनों देशों के लोगों के बीच कमज़ोर हुए संपर्कों को फिर से मजबूत करने में मदद मिलेगी।

मोदी-शी बैठक का व्यापक महत्व इसके राजनीतिक संदेश में है। दोनों में से कोई भी पक्ष अपने रणनीतिक हितों या बुनियादी मतभेदों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखता। इसके बजाय, जो नज़रिया उभर रहा है, वह "मैनेज्ड कॉम्पटिशन" (संभलकर की जाने वाली प्रतिस्पर्धा) का है, जिसमें मतभेदों को सीमित रखते हुए उन क्षेत्रों में सहयोग की कोशिश की जाती है, जहां दोनों के हित एक जैसे हैं।

शी की यात्रा, जो सात वर्षों में उनकी पहली भारत यात्रा है, इस बैठक को और महत्वपूर्ण बनाती है। इससे पता चलता है कि दोनों एशियाई शक्तियां उस रिश्ते को सुधारने के लिए राजनीतिक प्रयास करने को तैयार हैं, जो गलवान के बाद तेजी से बिगड़ा था।

हालांकि, भारत के लिए रिश्ते सामान्य होने का मतलब, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना 2020 से पहले की स्थिति में लौटना नहीं हो सकता। नई दिल्ली यह सुनिश्चित करना चाहेगी कि बेहतर आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों को सीमा पर भी ठोस प्रगति का समर्थन मिले। वहीं, बीजिंग के लिए भारत का विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए एलएसी पर लगातार शांति बनाए रखना और भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाना जरूरी होगा।

इसलिए मोदी-शी बैठक से कोई शानदार समझौता या ऐतिहासिक समाधान नहीं निकला है। इसका महत्व धीरे-धीरे होने वाले सुधारों में है। यह बैठक संबंधों में स्थिरता लाने की प्रक्रिया को मजबूत करती है और सीमा, व्यापार, संपर्क तथा द्विपक्षीय संबंधों के अन्य क्षेत्रों पर आगे बातचीत के लिए गुंजाइश बनाती है।

असली परीक्षा अब शुरू होती है। अगर मोदी और शी के बीच बनी राजनीतिक समझ एलएसी पर लगातार शांति, बेहतर आर्थिक लेन-देन और दोनों देशों के लोगों के बीच बढ़ते संपर्क में बदलती है, तो शनिवार की बैठक को भविष्य में भारत-चीन संबंधों में नए बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा सकता है।

सऊदी अरब ने कच्चे तेल की "ईस्ट -वेस्ट" पाइप लाइन बंद की

यह पाइप लाइन कच्चे तेल की आपूर्ति के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराती है

रियाद, 12 सितंबर। सऊदी अरब ने अपनी रणनीतिक 'ईस्ट-वैस्ट' कच्चे तेल की पाइपलाइन को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया है। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक, इस पाइपलाइन को एक दिन पहले रियाद और मदीना क्षेत्रों में कई हमलों का निशाना बनाया गया था। हालांकि, मंत्रालय ने हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं बताई है और न पाइपलाइन को हुए नुकसान की जानकारी दी है।

■ पाइप लाइन बंद करने का निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब सऊदी अरब का तेल उत्पादन 1990 के बाद न्यूनतम स्तर पर है। दूसरी ओर सऊदी अरब तथा ओपेक के अन्य देश उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहे थे।

ईरान सरकार के अंतरराष्ट्रीय समाचार नेटवर्क प्रेस टीवी के अनुसार, 'ईस्ट-वैस्ट' पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी क्षमता करीब 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। यह देश के तेल क्षेत्रों को लाल सागर स्थित निर्यात टर्मिनलों से जोड़ती है और फारस की खाड़ी से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराती है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ने के बाद इस पाइपलाइन की रणनीतिक अहमियत और बढ़ गई है। सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासिर ने पिछले महीने कहा था कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने के प्रभाव को कम करने में इस पाइपलाइन ने आपातकालीन तेल भंडार जारी करने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सऊदी अरब के लाल सागर स्थित तेल निर्यात मार्ग पर भी दबाव बढ़ रहा है। यमन की ओर से सऊदी तेल ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हमलों और समुद्री नाकेबंदी की घोषणा के बाद क्षेत्र में तेल परिवहन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

गौरतलब है कि जुलाई में यमन की सेना ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा करते हुए इसे घेराबंदी के बदले घेराबंदी की रणनीति बताया था।

पाइपलाइन बंद करने का फैसला ऐसे समय में आया है, जब सऊदी अरब के कच्चे तेल उत्पादन में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के अनुसार, अगस्त में सऊदी अरब का तेल उत्पादन घटकर करीब 62.4 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जबकि जुलाई में यह लगभग 81 लाख बैरल प्रतिदिन था। यह 1990 के बाद सऊदी तेल उत्पादन का सबसे निचला स्तर बताया जा रहा है। यह गिरावट ऐसे समय में हुई है, जब सऊदी अरब और ओपेक के अन्य देश तेल उत्पादन बढ़ाने की योजना पर आगे बढ़ रहे थे।

भाजपा ने दो चुनावों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पद के एकमात्र चेहरे के रूप में पेश करने से परहेज किया है। हालांकि वे सरकार का सबसे प्रमुख चेहरा बने हुए हैं और लगातार व्यापक जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सामूहिक नेतृत्व पर जोर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं को चुनाव प्रचार के चेहरों के रूप में गिनाया है, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम फैसले का अधिकार संसदीय बोर्ड पर छोड़ा गया है।

सूत्रों के अनुसार, भाजपा के चुनाव प्रचार का मुख्य आधार "डबल इंजन" सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, सुशासन, कानून-व्यवस्था में सुधार, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास और लाभार्थियों तक पहुंच बनाना होगा। 17 सितंबर से शुरू होने वाले एक महीने के "सेवा संकल्प" और "सुशासन" अभियानों के जरिए, इन संदेशों को 1.7 लाख से अधिक बूथों तक घर-घर पहुंचाया जाएगा। इन अभियानों में महिलाओं, युवाओं, जिनमें नई पीढ़ी (जैन ज़ैड) की चिंताएं भी शामिल हैं, किसानों और गरीबों को सरकारी योजनाओं से मिले लाभ को प्रमुखता से बताया जाएगा और विपक्ष के प्रचार का जवाब दिया जाएगा। जातिगत संतुलन को ध्यान में रखते हुए संगठन में नियुक्तियां करना भी पार्टी की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आने वाले हफ्तों और महीनों में भाजपा के कई बड़े नेता व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। योगी आदित्यनाथ प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए, अपने जिला दौरों को जारी रखेंगे। विनोद तावड़े समीक्षा दौरों पर जाएंगे, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और गृह मंत्री अमित शाह भी रैलियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।

"सेवा संकल्प" कार्यक्रमों में सेवा गतिविधियाँ, लाभार्थियों के साथ संवाद, सांस्कृतिक संपर्क और सड़क स्तर पर जनसंपर्क अभियान भी आयोजित किए जाएंगे।

विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अन्य संगठनों के साथ समन्वय बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन का विस्तार, स्थानीय स्तर पर पार्टी के प्रदर्शन की जानकारी जुटाना, कार्यकर्ताओं में अनुशासन और व्यापक जनसंपर्क अभियानों पर ध्यान केन्द्रित करना है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908